general education level relates to 30th June, 1991 and is given below:

	Number (in lakhs)
Total	30.8
Total Educated (Matric & above)	17.8
(i) Matric . . .	10.0
(ii) Intermediate/Higher Secondary . . .	5.1
(iii) Graduates & above .	2.7

The date on duration of stay of the job-seekers on the live register of employment exchanges are not maintained. Placement of persons registered depends on the demand made with the employment exchanges from time to time. The Eighth Five Year Plan however envisages generation of additional employment opportunities to the tune of 8 to 9 million every year, on an average, with a view to achieving a situation of near full employment over a decade.

ग्रामीण विकास के लिए कम धनराशि का आबंटन

*135. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए गत वर्ष की तुलना में कम धनराशि आबंटित की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर राज्य-वार कितना खर्च किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1991–92 के संशोधित अनुमान में 3000 करोड़ रुपये के मुकाबले 1992–93 के दौरान योजना में ग्रामीण विकास के लिए बजट अनुमान में 3100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(ख) बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के अनुसार 1989–90, 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
बजट अनुमान	2213.00	3129.08	3508.00
संशोधित अनुमान	3095.38	2975.01	3008.00

(ग) वर्ष 1989–90, 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं पर किए गए खर्च की प्रतिशतता विवरण I से विवरण V में दी गई है ।

विवरण–I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर किए गए राज्यवार खर्च का प्रतिशत

राज्य	खर्च का प्रतिशत			
	1989–90	1990–91	1991–92	(अनंतिम)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश . .	109.47	135.84	127.45	

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	59.48	59.34	64.13	
असम	115.50	117.26	91.00	
बिहार	84.95	90.23	85.71	
गोआ	112.39	109.12	83.62	
गुजरात	116.65	103.32	129.94	
हरियाणा	214.60	184.90	156.37	
हिमाचल प्रदेश	290.22	212.02	205.55	
जम्मू व कश्मीर	161.87	190.36	163.92	
कर्नाटक	86.70	89.32	87.63	
केरल	102.97	109.21	115.45	
मध्य प्रदेश	91.29	114.80	136.50	
महाराष्ट्र	101.67	97.08	101.58	
मणिपुर	224.22	313.19	397.51	
मेघालय	102.32	132.46	142.67	
मिजोरम	102.89	109.82	91.76	
नागालैंड	128.96	125.47	126.83	
उड़ीसा	84.98	100.89	121.38	
पंजाब	272.93	229.08	213.76	
राजस्थान	96.37	101.38	126.00	
सिक्किम	126.51	95.02	140.39	
तमिलनाडु	104.43	101.41	96.27	
त्रिपुरा	260.23	230.34	283.51	
उत्तर प्रदेश	104.41	115.22	123.08	
पश्चिम बंगाल	115.13	107.04	113.82	
अंडमान व निकोबार	105.38	84.27	83.25	
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	
दादरा व नागर हवेली	100.10	94.68	88.85	
दिल्ली	88.08	89.71	60.27	
दमन व दीव	77.86	76.74	57.16	
लक्षद्वीप	28.14	183.60	160.80	
पांडिचेरी	109.23	125.49	102.91	
अखिल भारत :	102.36	108.32	113.84	

विवरण–II

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर किए गए खर्च का प्रतिशत–राज्यवार ।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989–90	1990–91	1991–92
1.	आन्ध्र प्रदेश	95.32	97.82	98.11
*2.	अरूणाचल प्रदेश	52.62	70.07	658.33*
3.	असम	85.77	118.67	115.27
4.	बिहार	81.86	119.94	95.96
5.	गोआ	85.92	129.28	103.13
6.	गुजरात	92.27	101.30	122.60
7.	हरियाणा	95.28	102.50	90.28
8.	हिमाचल प्रदेश	85.61	117.82	94.04
9.	जम्मू व कश्मीर	101.99	81.82	82.16
10.	कर्नाटक	86.46	100.46	98.75
11.	केरल	100.26	112.24	115.25
12.	मध्य प्रदेश	80.27	104.62	145.78
13.	महाराष्ट्र	100.31	98.12	111.74
14.	मणीपुर	100.05	105.62	140.35
15.	मेघालय	24.07	138.38	78.64
16.	मिजोरम	100.35	99.97	113.08
17.	नागालैंड	100.00	100.00	110.95
18.	उडीसा	81.81	100.83	134.29
19.	पंजाब	102.69	76.30	64.15
20.	राजस्थान	83.27	129.94	139.37
21.	सिक्किम	78.81	126.81	97.52
22.	तमिलनाडु	101.60	97.98	140.28
23.	त्रिपुरा	94.15	103.07	106.92
24.	उत्तर प्रदेश	99.06	94.30	108.08
25.	पश्चिम बंगाल	92.44	85.86	144.01
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	58.59	130.31	155.52
27.	चंडीगढ	65.74	43.67	0.00
28.	दादरा व नागर हवेली	102.88	82.40	131.95
29.	दमन व द्वीव	61.86	61.74	621.69*
30.	दिल्ली	48.23	61.72	0.00
31.	लक्षद्वीप	75.36	69.84	184.98
32.	पांडेचेरी	106.95	68.14	244.72
	कुल :	91.25	102.72	115.50

*पिछले वर्ष की भारी मात्रा में शेष बची राशि का वर्ष के दौरान इस्तेमाल किए जाने के कारण ।

विवरण-III

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर हुए राज्यवार खर्च का प्रतिशत ।

क्रम संख्या	राज्य केंन्द्र शासित क्षेत्र	1989–90	1990–91	1991–92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	127.47	100.00	111.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	79.76	80.82	64.72
3.	असम	108.73	86.01	128.61
4.	बिहार	108.73	40.32	61.15
5.	गोवा	53.40	75.00	143.64
6.	गुजरात	74.13	93.24	74.65
7.	हरियाणा	66.89	91.85	82.48
8.	हिमाचल प्रदेश	100.16	100.34	75.08
9.	जम्मू व कश्मीर	114.20	8.20	25.42
10.	कर्नाटक	116.78	88.40	87.06
11.	केरल	93.09	141.71	114.86
12.	मध्य प्रदेश	120.30	103.40	118.80
13.	महाराष्ट्र	116–70	82.47	73.27
14.	मणिपुर	99.58	99.84	76.62
15.	मेंघालय	90.79	90.00	79.52
16.	मिजोरम	193.16	99.32	135.66
17.	नागालैंड	123.22	61.52	49.76
18.	उड़ीसा	61.27	127.40	87.27
19.	पंजाब	154.90	129.82	304.01
20.	राजस्थान	113.99	104.66	100.00
21.	सिक्किम	107.53	91.13	102.96
22.	तमिलनाडु	132.19	141.95	120.90
23.	त्रिपुरा	116.09	34.31	34.86
24.	उत्तर प्रदेश	128.94	89.75	73.69
25.	पश्चिम बंगाल	97.49	83.29	76.21
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	116.25	159.00	100.00
27.	चंडीगढ*	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा व नागर हवेली*	0.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	100.00

*कोई आबंटन नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	1989–90	1990–91	1991–92
1	2	3	4	5
30	लक्षद्वीप	40.00	45.00	50.00
31	पांडिचेरी	96.15	25.00	7.69
32	दमन व द्वीप . . .	100.00	100.00	100.00
		111.33	89.01	88.43

विवरण–IV

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर राज्यवार किए गए खर्च का प्रतिशत

क्रम संख्या	राज्य	1989–90	1990–91	1991–92
1	आंध्र प्रदेश . . .	102.6	103.5	110.7
2	बिहार	107.2	61.7	62.6
3	गुजरात	106.1	111.4	98.7
4	हरियाणा	113.9	112.9	84.2
5	जम्मू व कश्मीर . . .	104.1	66.7	154.4
6	कर्नाटक	83.4	83.3	95.9
7	मध्य प्रदेश	85.7	83.9	117.7
8	महाराष्ट्र	101.5	94.2	71.8
9	उड़ीसा	86.6	87.8	115.2
10	राजस्थान	100.9	124.0	94.4
11	तमिलनाडु	106.6	112.5	102.1
12	उत्तर प्रदेश	95.8	89.3	98.4
13	पश्चिम बंगाल . . .	93.8	71.5	54.6
		97.4	92.9	94.5

विवरण–V

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास पर किए गए खर्च का प्रतिशत–राज्यवार

क्रम संख्या	राज्य	1989–90	1990–91	1991–92
1	गुजरात	123.6	113.1	124.7
2	हरियाणा	104.8	110.7	81.0
3	हिमाचल प्रदेश	107.3	101.0	93.8
4	जम्मू व कश्मीर	102.3	100.1	101.8
5	राजस्थान	96.2	123.7	96.0
		99.0	119.3	96.3

Stoppage of Hindi News Bulletin in Punjab

*136. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the telecast of the Hindi news bulletin on the National Network of Doordarshan likely to be stopped in Punjab; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Relief for losses suffered by Indian Community in the U.S.A.

*137. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Community in the U.S.A. is going to seek relief from the U.S. Government for the losses suffered by them in their business due to the recent riots that took place in Los Angeles; and

(b) if so, what is the reaction of U.S. Government in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The affected members of the Indo-American community have sought relief from local, State and Federal authorities as permissible under U.S. laws.

(b) U.S. authorities at the local, State and Federal levels have given assurances that they will facilitate insurance claims and other compensation.

Coal-dump fires at the collieries of ECL

*138. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently there have been several coal-dump-fires at different collieries of ECL; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MIN-